Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

30 जून 2025

NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिमला में 196वीं ESIC बैठक की अध्यक्षता की और सामाजिक सुरक्षा सुधार के लिए प्रमुख योजनाएं शुरू कीं।

जून 2025 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 196वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और नियोक्ता अनुपालन को आसान बनाने पर केंद्रित प्रमुख नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला गया।

- **उच्च स्तरीय ESIC बैठक की अध्यक्षता डॉ. मनसुख मंडाविया ने की, जिनके पास युवा मामले और खेल मंत्रालय का भी प्रभार है। इस बैठक का उद्देश्य श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) के तहत मौजूदा योजनाओं का आकलन करना और ESIC की पहुंच और प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए नई रणनीतियां पेश करना था।**

- **बैठक का एक प्रमुख आकर्षण SPREE पहल की पुनः शुरूआत थी - नियोक्ता/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना। यह योजना सामाजिक बीमा प्रणाली के तहत अधिक व्यवसायों और श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करके पूरे भारत में ESIC कवरेज का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन की गई है।**

- **पुनः शुरू की गई SPREE योजना 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि के दौरान, स्वैच्छिक पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सहायता तंत्र प्रदान किए जाएंगे, जिससे ESIC नेटवर्क में वृद्धि होगी।**

Key Points:-

(i) बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय एमनेस्टी स्कीम 2025 को मंजूरी देना था, जो नियोक्ताओं के लिए एक बार का विवाद समाधान ढांचा है। यह विंडो 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक खुली रहेगी, जिससे व्यवसायों को बिना किसी दंड के लंबित अनुपालन मुद्दों को हल करने की अनुमति मिलेगी।

(ii) ESIC ने अपने क्षतिपूर्ति ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार की भी घोषणा की है। मौजूदा ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम को सरलीकृत फ्लैट दर संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य चूककर्ता नियोक्ताओं पर कानूनी और वित्तीय बोझ को कम करना और आसान समाधान को बढ़ावा देना है।

(iii) हर्जाने की अधिकतम दर में काफी कमी की गई है - 25% प्रति वर्ष से घटाकर हर महीने डिफ़ॉल्ट राशि पर 1% कर दिया गया है। इस बदलाव से अनुपालन में वृद्धि होने और छोटे और मध्यम उद्यमों पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है।

2. अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया।

29 जून 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में नव-स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिससे हल्दी किसानों की चार दशक पुरानी मांग पूरी हुई और निवेश, ब्रांडिंग और निर्यात फोकस के साथ भारत के हल्दी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया।

• अपने संबोधन में, श्री शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की "हल्दी की राजधानी" के रूप में मशहूर निज़ामाबाद में अब खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एकीकृत प्रयास देखने को मिलेंगे - जिससे बिचौलियों को प्रभावी रूप से खत्म किया जा सकेगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 के चुनावी वादे के अनुरूप है जिसमें उन्होंने हल्दी उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया था।

• उन्होंने कहा कि हल्दी की कीमतें हाल ही में ₹18,000-₹19,000 प्रति क्विंटल के बीच रही हैं और अगले तीन वर्षों में ₹6,000-₹7,000 की और वृद्धि का वादा किया। 2023-24 में, हल्दी लगभग 3 लाख हेक्टेयर में उगाई गई, जिससे देश भर में लगभग 10.74 लाख टन फसल पैदा हुई।

• अमित शाह जी ने तेलंगाना में फसल की गुणवत्ता, अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और किसानों की आय में सुधार के लिए ₹200 करोड़ के केंद्रीय आवंटन का भी खुलासा किया। बोर्ड का लक्ष्य जीआई-टैग वाली जैविक हल्दी सहित एक एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है और 2030 तक 1 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखना है।

Key Points:-

(i) उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार, भाजपा सांसद के. लक्ष्मण और डी. अरविंद मौजूद थे। डी. अरविंद ने अपने लोकसभा चुनाव के वादे को पूरा करने पर गर्व व्यक्त किया, जबकि स्थानीय प्रचारकों ने पूर्व विधायक के कैंप कार्यालय को बोर्ड के अस्थायी परिसर में बदलने पर प्रकाश डाला।

(ii) नया बोर्ड किसानों के कौशल विकास, जियोटैगिंग सहायता प्रदान करेगा और वैश्विक स्तर पर भारत के हल्दी ब्रांड को मजबूत करेगा। श्री शाह ने हल्दी को एक "चमत्कारी औषधि" बताया, इसके एंटीवायरल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीकैंसर लाभों पर जोर दिया।

(iii) यह उद्घाटन भारत के हल्दी उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है - जो खंडित उत्पादन प्रणालियों से वैज्ञानिक रूप से समर्थित, वैश्विक रूप से जुड़े आपूर्ति नेटवर्क में परिवर्तन को दर्शाता है जो किसान कल्याण को बढ़ाता है और निर्यात महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है।

3. MoRTH ने 1 जनवरी 2026 से सभी दोपहिया वाहनों के लिए ABS और दोहरे हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 जनवरी, 2026 से उत्पादित सभी दोपहिया वाहनों पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य करने वाले मसौदा नियम जारी किए हैं। दुर्घटनाओं को कम करने और सवार की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस उपाय में हर नए वाहन की खरीद के साथ दो BIS-प्रमाणित हेलमेट की आवश्यकता भी शामिल है।

• इससे पहले, ABS केवल 125cc से ज़्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर ही अनिवार्य था। नए नियमों के अनुसार, इंजन के आकार की परवाह किए बिना, हर नए दोपहिया वाहन में 1 जनवरी 2026 से ABS लगाना अनिवार्य

है। यह ऐतिहासिक निर्णय सड़क सुरक्षा पर MoRTH के गहन ध्यान को दर्शाता है।

• ABS के अतिरिक्त, डीलरशिप को अब प्रत्येक खरीद पर दो बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट शामिल करने होंगे - एक सवार और एक पीछे बैठने वाले के लिए - जिससे दोनों यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

Key Points:-

(i) आंकड़े बताते हैं कि 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44% से अधिक का योगदान दोपहिया वाहनों का था। अध्ययनों से पता चलता है कि ABS आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहिया लॉक को रोककर दुर्घटना के जोखिम को 35-45% तक कम कर सकता है, विशेष रूप से गीली या असमान सतहों पर।

(ii) भारत ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.96 करोड़ दोपहिया वाहन बेचे; लगभग 78% सब-125 cc मॉडल थे। चूंकि ABS एंट्री-लेवल बाइक में भी मानक बन गया है, इसलिए बाइक श्रेणी और ABS प्रकार के आधार पर स्टिकर की कीमतें ₹2,500-7,000 तक बढ़ सकती हैं।

4. प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में भारत के पहले 5 गीगावाट घंटे स्वचालित BESS संयंत्र का उद्घाटन किया।

27 जून 2025 को, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बेंगलुरु के बिदादी औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) सुविधा का उद्घाटन किया। 5GWh वार्षिक क्षमता वाला यह स्वचालित संयंत्र भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ग्रिड स्थिरता और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

• PACEDigitek (पूर्व में Lineage Power) द्वारा संचालित, बेंगलुरु प्लांट भारत की सबसे बड़ी BESS निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसमें पूरी तरह से स्वचालित "सेल-टू-पैक" असेंबली लाइन है। यह सटीक इंजीनियरिंग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

• 5GWh क्षमता सीधे सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को संबोधित करती है, ग्रिड लचीलापन बढ़ाती है, पीक लोड का प्रबंधन करती है और आवृत्ति को स्थिर करती है। MoNRE ने 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे BESS उस लक्ष्य के लिए आवश्यक हो गया है।

Key Points:-

(i) मंत्री जोशी ने 30GWh BESS परियोजनाओं को गति देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना के तहत अतिरिक्त ₹5,400 करोड़ की घोषणा की - जो 13.2GWh का समर्थन करने वाले मौजूदा ₹3,700 करोड़ के वित्तपोषण को बढ़ाएगा। ऊर्जा भंडारण में कुल निवेश 2032 तक ₹4.79 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

(ii) ऊर्जा भंडारण के लिए वैश्विक केंद्र बनने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, जोशी ने कहा कि 2032 तक 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 47 गीगावाट BESS क्षमता जोड़ने की योजना है, जिसे मजबूत नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन प्राप्त है।

(iii) नई सुविधा से उच्च-मूल्य वाली नौकरियां पैदा होने और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

5. जयंत चौधरी ने भारत के कार्यबल परिदृश्य को नया आकार देने के लिए "भविष्य के लिए कौशल" रिपोर्ट जारी की।

27 जून 2025 को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में "भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य को बदलना" शीर्षक से रिपोर्ट का अनावरण किया। प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा विकसित इस रिपोर्ट में भविष्य की नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक तत्काल सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।

• रिपोर्ट में हाल ही के डेटासेट जैसे कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24, PMKVY 4.0 और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) डैशबोर्ड शामिल हैं। यह भारत की वर्तमान कार्यबल संरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कवरेज और शिक्षा के स्तर का एक नैदानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है - जो नौकरी बाजारों के साथ कौशल संरेखण में प्रमुख पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

• निष्कर्षों के अनुसार, भारत का लगभग 88% कार्यबल कम योग्यता वाली भूमिकाओं में लगा हुआ है, जबकि केवल 10-12% ही उच्च कौशल वाले पदों पर हैं।

• इसके अलावा, 10% से भी कम श्रमिकों के पास माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा है, और आधे से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा स्तर या उससे नीचे हैं। यह शैक्षिक अंतर रोज़गार और आय क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में भारत में कौशल-नौकरी के बीच गंभीर असंतुलन को दर्शाया गया है: उच्च शिक्षित युवा अक्सर कम कौशल वाली नौकरियों में काम कर रहे हैं, और कम योग्यता वाले व्यक्ति तकनीकी रूप से मांग वाली भूमिकाओं में हैं। यह गलत आवंटन श्रम उत्पादकता को कम करता है, नवाचार को हतोत्साहित करता है, और भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करता है, खासकर तब जब देश उभरते क्षेत्रों में अपने औपचारिक कार्यबल का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है।

(ii) इसमें पाँच मुख्य क्षेत्रों की भी पहचान की गई है - IT/ITeS, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य सेवा और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य - जो भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण कवरेज का 66% से अधिक हिस्सा हैं। हालाँकि, क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी स्पष्ट हैं। जबकि केरल और चंडीगढ़ में स्तर 3 और 4 प्रशिक्षित श्रमिकों की उच्च हिस्सेदारी है, बिहार और असम जैसे राज्य कौशल परिणामों में पिछड़ रहे हैं।

(iii) इन अंतरों को पाटने के लिए, रिपोर्ट में राष्ट्रीय रोजगार सूचकांक बनाने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने, प्रमाणित भर्ती को प्रोत्साहित करने और अनौपचारिक शिक्षा को मान्यता देने का प्रस्ताव है। मंत्री जयंत चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को विजन 2047 के लिए तैयार करने के लिए भारत की कौशल नीतियों को आपूर्ति-संचालित मॉडल से मांग-आधारित, उद्योग-संरेखित रणनीतियों में बदलना होगा।

INTERNATIONAL

1. भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात को केवल न्हावा शेवा बंदरगाह तक सीमित कर दिया है, तथा सभी स्थल मार्ग से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

27-29 जून 2025 तक, भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बांग्लादेश से ज़मीनी रास्ते से कुछ जूट और उससे जुड़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह अनिवार्य कर दिया है कि ऐसे आयात सिर्फ़ न्हावा शेवा बंदरगाह से ही किए जाएँगे। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य नियामक निगरानी को मज़बूत करना और घरेलू जूट उद्योग की सुरक्षा करना है।

• DGFT अधिसूचना बांग्लादेश से निर्यात की एक श्रृंखला को कवर करती है - जिसमें जूट उत्पाद, फ्लैक्स टो और अपशिष्ट, कच्चा या सड़ा हुआ जूट, जूट यार्न (एकल और बहु-गुना), और बुने हुए/बिना ब्लीच किए हुए कपड़े शामिल हैं। इन वस्तुओं को अब भारत-बांग्लादेश के सभी भूमि क्रॉसिंग पॉइंट्स, साथ ही अधिकांश समुद्री और हवाई बंदरगाहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

• जबकि भूमि बंदरगाह बंद हैं, महाराष्ट्र में न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति है। यह एकल-बंदरगाह नीति सख्त गुणवत्ता जांच, धोखाधड़ी नियंत्रण और एंटी-डंपिंग सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सक्षम बनाती है।

Key Points:-

(i) बांग्लादेश सालाना लगभग 150 मिलियन डॉलर मूल्य के जूट उत्पादों का निर्यात करता है - जो उसके जूट निर्यात का लगभग 23% है, जिसमें 117 निर्यातक भूमि मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वैकल्पिक समुद्री रसद लागत बढ़ा सकती है और डिलीवरी में देरी कर सकती है, जिससे बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो सकती है।

(ii) यह प्रतिबंध भारत द्वारा बांग्लादेशी परिधानों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अप्रैल-मई में लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप है, और यह भारत के पूर्वोत्तर संपर्क के संबंध में बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की टिप्पणियों से उत्पन्न राजनयिक तनाव के बाद लगाया गया है।

(iii) भारत का लक्ष्य अपने जूट उद्योग को डंप किए गए और सब्सिडी वाले आयात से बचाना है। इस कदम से व्यापार की गतिशीलता को नया आकार मिलने, द्विपक्षीय व्यापार शर्तों को मजबूत करने और निगरानी वाले समुद्री चैनलों के माध्यम से जूट रूटिंग को स्थानांतरित करने, नियामक निरीक्षण और पारस्परिक निर्यात उपायों को मजबूत करने की उम्मीद है।

2. सलखान जीवाश्म पार्क को UNESCO की संभावित सूची में शामिल किया गया, जिसमें 1.4 अरब वर्ष पुराने भूवैज्ञानिक चमत्कार को दर्शाया गया।

22 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को आधिकारिक तौर पर UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया। 25 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म मौजूद हैं, जो पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन और प्राकृतिक

इतिहास के अध्ययन में इसके वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हैं।

• कैमूर रेंज में रॉबर्ट्सगंज के पास स्थित, सलखन जीवाश्म पार्क लगभग 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म हैं, जिनके लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने होने का अनुमान है - जो उन्हें पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने ज्ञात साक्ष्यों में से एक बनाता है।

• संभावित सूची में शामिल होना विश्व धरोहर का दर्जा पाने की दिशा में पहला औपचारिक कदम है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के नेतृत्व में वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित एक डोजियर अब यूनेस्को समीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा; दो साल के भीतर पूर्ण नामकरण की उम्मीद है।

• पार्क की स्ट्रोमेटोलाइट संरचनाएं - डोमल, कॉलमनर और स्ट्रेटीफॉर्म - प्रीकैम्ब्रियन युग में लगातार पर्यावरणीय परिवर्तनों को पकड़ती हैं, विशेष रूप से महान ऑक्सीकरण घटना के दौरान, जिससे जीवाश्म रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण अंतर भर जाता है।

Key Points:-

(i) UNESCO की मान्यता के साथ, क्षेत्रीय पर्यटन में वृद्धि होने का अनुमान है। साइट के शामिल होने से इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो सकती है, रोजगार पैदा हो सकता है और अविकसित विंध्य क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

(ii) भूवैज्ञानिक अन्वेषण 1930 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें 2002 और उसके बाद के शोध में उल्लेखनीय योगदान दिया गया। कार्यशालाओं और पुरा-वैज्ञानिक अनुसंधान सहित उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके स्थायी वैज्ञानिक मूल्य को रेखांकित करते हैं।

(iii) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन अवसंरचना योजनाओं, पारिस्थितिकी विकास निधियों के साथ इस पहल का समर्थन किया है, तथा एक मजबूत नामांकन डोजियर तैयार करके UNESCO की स्थायी सूची को सुरक्षित करने की दिशा में एक केंद्रित प्रयास किया है।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने जनवरी 2026 से KYC को मजबूत करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त AePS नियमों की घोषणा की।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी इन नियमों का उद्देश्य मज़बूत KYC अनुपालन, ऑपरेटर सत्यापन और बैंकिंग टचपॉइंट्स की वास्तविक समय निगरानी को अनिवार्य करके बढ़ते धोखाधड़ी जोखिमों से निपटना है।

• AePS में पहचान की चोरी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने निर्देश दिया है कि सभी AePS टचपॉइंट ऑपरेटर (ATO) जैसे बैंक मित्र और बीसी एजेंट्स का ऑनबोर्डिंग से पहले पूर्ण KYC (अपने ग्राहक को जानिए) और ग्राहक सतर्कता प्रक्रिया (CDD) के तहत सत्यापन किया जाए। अधिग्रहण करने वाले बैंकों को RBI के 2016 के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार KYC मानदंडों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

• वे ऑपरेटर जो लगातार तीन महीने तक निष्क्रिय रहते हैं, उन्हें सेवाएं फिर से शुरू करने से पहले दोबारा KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह नीति निष्क्रिय आईडी का

दुरुपयोग रोकने के लिए बनाई गई है और यह सुनिश्चित करेगी कि केवल सक्रिय रूप से निगरानी किए गए एजेंट ही सेवाएं दे सकें।

• RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक AePS ऑपरेटर केवल एक अधिग्रहण बैंक से ही जुड़ा हो सकता है। इस कदम से विभिन्न बैंकों के साथ कई पंजीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिससे निगरानी आसान होगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। यह पारदर्शिता को बढ़ाएगा और बैंकों को बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा।

Key Points:-

(i) ऑनबोर्डिंग नियमों के अतिरिक्त, अधिग्रहण बैंक को जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली लागू करनी होगी। इसमें ऑपरेटर की जोखिम प्रोफ़ाइल, भौगोलिक क्षेत्र और लेनदेन के इतिहास के आधार पर सीमाएं तय की जाएंगी। नियमित समीक्षा और रीयल-टाइम अलर्ट से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और रोकथाम संभव होगी।

(ii) RBI ने तकनीकी और API सुरक्षा उपायों को भी अनिवार्य किया है। AePS के लिए उपयोग किए जा रहे API केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही सीमित रहेंगे और इन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से अलग रखा जाएगा। यह निर्णय हालिया वर्षों में बढ़े AePS साइबर फ्रॉड को देखते हुए लिया गया है, जो 2023 में कुल वित्तीय साइबर अपराधों का लगभग 11% था।

(iii) इन सभी दिशानिर्देशों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारी किया गया है। हर साल भारत में 1,100 करोड़ से अधिक AePS लेनदेन होते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए 2026 से लागू हो रहे ये नियम आधार-लिंक्ड बैंकिंग को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम हैं।

2. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया।

27 जून, 2025 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित चार सहकारी बैंकों को दंडित किया। यह कार्रवाई सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के भीतर नियामक अनुपालन और शासन पर RBI के बढ़ते फोकस को उजागर करती है।

• बैंकिंग विनियमन (BR) अधिनियम, 1949 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए RBI ने विशिष्ट विनियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए चार शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) पर मौद्रिक दंड लगाया है। इन दंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहकारी बैंक पारदर्शिता, ऋण देने की प्रथाओं और ग्राहक सत्यापन मानदंडों के संबंध में RBI की पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

• दंडित बैंकों में तेलंगाना में हैदराबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (HDCCB) और करीमनगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (KDCCB), आंध्र प्रदेश में चित्तूर सहकारी टाउन बैंक (CCTB) और कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित कर्नाटक सहकारी बैंक (KCB) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक बैंक जोखिम प्रशासन और KYC अनुपालन से संबंधित एक या अधिक विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया।

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 20 का उल्लंघन करने के लिए HDCCB और KDCCB दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये

धाराएं संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम देने पर प्रतिबंध लगाने और सहकारी संस्थाओं के भीतर जिम्मेदार ऋण आवंटन सुनिश्चित करने से संबंधित हैं।

Key Points:-

(i) CCTB (चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक) पर भी RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (USBs) पर लागू होते हैं। ये उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा अनिवार्य किए गए विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दायित्वों का पालन करने में विफलता से संबंधित थे।

(ii) KCB (कर्नाटक सहकारी बैंक) को भी BR अधिनियम की धारा 47A(1)(c), 46(4)(i) और 56 के तहत कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ा। इन प्रावधानों में सहकारी बैंकिंग परिचालन में आवश्यक परिचालन पारदर्शिता, शासन तंत्र और दस्तावेज़ीकरण मानकों के बारे में RBI के दिशानिर्देशों का पालन न करना शामिल है।

(iii) RBI द्वारा की गई यह नियामक कार्रवाई सहकारी बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दंड अन्य UCBs के लिए उचित परिश्रम बढ़ाने, मजबूत आंतरिक नियंत्रण अपनाने और पूर्ण विनियामक अनुपालन बनाए रखने की चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।

ECONOMY & BUSINESS

1. NSO रिपोर्ट से पता चलता है कि वित्त वर्ष 24 में भारत का कृषि उत्पादन ₹29.49 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

28 जून, 2025 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर अपनी वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि भारत का कृषि उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 29.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया - जो वित्त वर्ष 2012 से 54.6% की वृद्धि है।

- **कृषि और संबद्ध गतिविधियों से उत्पादन का सकल मूल्य (GVO) वित्त वर्ष 2012 में ₹19.08 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹29.49 लाख करोड़ हो गया (स्थिर मूल्य), जो बारह वर्षों में 54.6% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है।**

- **वर्तमान मूल्यों पर, सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 225% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2012 में ₹15.02 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹48.78 लाख करोड़ हो गया - जो इस क्षेत्र के बढ़े हुए आर्थिक योगदान को दर्शाता है।**

- **वित्त वर्ष 2024 में ₹15.95 लाख करोड़ के GVO के साथ फसल खंड प्राथमिक चालक बना रहा, जो कुल कृषि उत्पादन का 54.1% था। अनाज, फल और सब्ज़ियों ने फसल उत्पादन मूल्य का 52% से अधिक प्रतिनिधित्व किया।**

Key Points:-

(i) अनाजों में धान और गेहूँ ने अनाज की GVO में लगभग 85% का योगदान दिया। फलों की श्रेणी में, केला (₹47,000

करोड़) ने आम (₹46,100 करोड़) को पीछे छोड़ दिया, जबकि आलू ने वित्त वर्ष 24 में ₹37,200 करोड़ के साथ सब्जी की जी.वी.ओ. में शीर्ष स्थान हासिल किया।

(ii) फूलों की खेती में उत्पादन लगभग दोगुना हो गया, जो वित्त वर्ष 12 में ₹17,400 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹28,100 करोड़ हो गया। इसी तरह, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखी गई, जो भारत की कृषि-संबद्ध अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को दर्शाता है।

(iii) पांच कृषि महाशक्तियों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने वित्त वर्ष 24 में कुल अनाज उत्पादन GVO में लगभग 53% का योगदान दिया। उत्तर प्रदेश ने अपनी बढ़त बरकरार रखी, हालांकि इसका हिस्सा 18.6% (वित्त वर्ष 12) से थोड़ा कम होकर 17.2% (वित्त वर्ष 24) हो गया।

2. HDFC म्यूचुअल फंड ने ओपन मार्केट डील के जरिए सुंदरम फास्टनर्स में 0.65% हिस्सेदारी ₹137 करोड़ में हासिल की।

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की सहायक कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में जून 2025 में सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के 13.70 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो 0.65% हिस्सेदारी के बराबर है। ₹137.02 करोड़ का निवेश ₹1,000 के औसत शेयर मूल्य पर खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से किया गया, जिससे कंपनी में HDFC MF की कुल हिस्सेदारी 4.27% से बढ़कर 5.02% हो गई।

- **सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है, TVS समूह के तहत एक प्रमुख ऑटोमोटिव घटक आपूर्तिकर्ता है। 1966 में स्थापित, कंपनी घरेलू और वैश्विक ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) दोनों के लिए एक अग्रणी निर्माता बन गई है, जिसमें नवाचार, इंजीनियरिंग और विविध उत्पाद लाइनों के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा है।**

- **कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो फास्टनर्स, पावरट्रेन घटक, सिन्टर मेटल उत्पाद, रेडिएटर कैप्स, कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट्स, वॉटर पंप, ऑयल पंप और विंड एनर्जी कंपोनेंट्स तक फैला हुआ है। इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत मौजूदगी है, जिसमें भारत, चीन और यूरोप में उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं, और यह उत्तर अमेरिका तथा यूरोपीय बाजारों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।**

Key Points:-

(i) HDFC MF का रणनीतिक निवेश भारत के ऑटो सहायक क्षेत्र में व्यापक सुधार के बीच हुआ है, जो बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन और विविधतापूर्ण, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर वैश्विक बदलाव से प्रेरित है। सुंदरम फास्टनर्स की मजबूत बैलेंस शीट, निर्यात क्षमता और R&D में निवेश इसे क्षेत्रीय अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।

(ii) संबंधित बाजार घटना में, सिंगापुर स्थित क्यूब मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने क्यूब हाईवेज ट्रस्ट- जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvIT) है- में 0.59% हिस्सेदारी (लगभग 79.25 लाख यूनिट) ₹127.50 प्रति यूनिट की दर से ₹101 करोड़ में बेच दी।

(iii) क्यूब हाईवे ट्रस्ट, जो टोल सड़कों और राजमार्ग परिसंपत्तियों में निवेश करता है, InvITs के माध्यम से स्थिर रिटर्न चाहने वाले दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. केंद्र ने CBDT अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया।

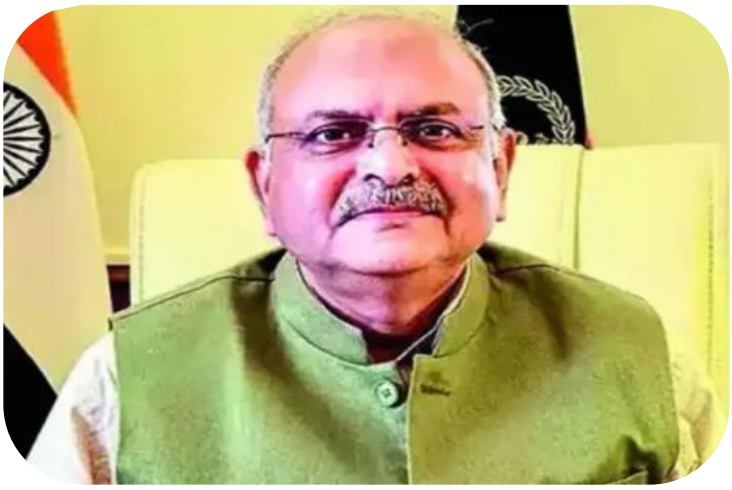

28 जून, 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक चलेगा, जो भारत के प्रत्यक्ष कर नेतृत्व में निरंतरता को मजबूत करेगा।

• 1988 बैच के IRS अधिकारी रवि अग्रवाल ने मूल रूप से जून 2024 में CBDT अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था और उन्हें जून 2025 तक अनुबंध के आधार पर बनाए रखा गया था। नवीनतम विस्तार, 1 जुलाई 2025 से प्रभावी, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में चल रहे सुधारों के बीच अनुभवी नेतृत्व को बनाए रखता है।

• विस्तार का एक प्रमुख कारण जटिल कर विवादों को सुलझाने में निरंतरता और कर न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आयकर अधिकारियों से पारदर्शिता, करदाता-अनुकूल प्रक्रियाओं और 577,000 से अधिक लंबित कर अपीलों के शीघ्र निपटान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

• उनके नेतृत्व में, CBDT आयकर विभाग के लिए नीति और प्रशासनिक नियोजन की देखरेख करता है, जिसमें वरिष्ठ नियुक्तियाँ, विभागीय स्थानांतरण और ओईसीडी और UN जैसे वैश्विक कर मंचों में प्रतिनिधित्व शामिल है। अग्रवाल की गहन विशेषज्ञता ने उन्हें वित्त मंत्रालय के एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में स्थापित किया है।

Key Points:-

(i) रवि अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति में अनुबंध के आधार पर अनुभवी IRS अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा जारी है, जिसमें नियमों में ढील दी गई है, जिससे पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे भी सेवा करने की अनुमति मिलती है। ये शर्तें कर तंत्र में विनियामक लचीलापन और संस्थागत स्मृति सुनिश्चित करती हैं।

(ii) अग्रवाल के नेतृत्व में CBDT आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्तों को प्रभावी पर्यवेक्षण करने, आकलन में प्रासंगिक पूछताछ सुनिश्चित करने और तुच्छ जांच नोटिसों को खत्म करने का निर्देश दे रहा है। यह कर प्रणाली में सरलता और पारदर्शिता के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।

(iii) अग्रवाल का अनुबंध विस्तार आयकर विभाग में 35 वर्षों से अधिक के उनके विशिष्ट करियर का समापन है और यह सर्वोच्च कर नीति निकाय के भीतर स्थिरता पर सरकार के फोकस को पुष्ट करता है। उनके निरंतर नेतृत्व को वित्त वर्ष 2025-26 में कर अनुपालन और विवाद समाधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

SPORTS

1. ICC ने जुलाई 2025 से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नई खेल स्थितियों को मंजूरी दी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में खेल की स्थितियों में व्यापक बदलाव पेश किए हैं, जो जून-जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य खेल की गति में सुधार करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाना और नई तकनीक और प्रक्रियात्मक अपडेट के माध्यम से निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

• टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव करते हुए, ICC ने 17 जून, 2025 से ओवरों के बीच 60 सेकंड का स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। अगर कोई फील्डिंग टीम एक पारी में दो बार से ज़्यादा इस सीमा को पार करती है, तो उस पर पाँच रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। यह नियम तेज़ ओवर रेट को बढ़ावा देता है और मैच की गति को बनाए रखता है।

• 2 जुलाई 2025 से वनडे मैचों में अंतिम 16 ओवरों के लिए केवल एक गेंद का उपयोग किया जाएगा। 34वें ओवर के बाद, कप्तान को खेल जारी रखने के लिए इस्तेमाल की गई दो गेंदों में से एक को चुनना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य रिवर्स स्विंग को बहाल करना और डेथ ओवरों के दौरान बल्ले-गेंद के बीच प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना है।

• ICC ने बाउंड्री कैच से जुड़े नियम को स्पष्ट किया है। अब फील्डर बाउंड्री से बाहर हवा में रहते हुए गेंद से सिर्फ़ एक बार ही संपर्क कर सकते हैं और कैच पूरा करने के लिए उन्हें पूरी तरह रस्सी के अंदर उतरना होगा। इससे ग्रे एरिया खत्म हो जाता है और सभी मैचों और फॉर्मेट में एक समान व्याख्या सुनिश्चित होती है।

Key Points:-

(i) निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि बल्लेबाज को एक मोड में आउट करार दिया जाता है, जैसे कि कैच, तो फील्डिंग टीमें अभी भी दूसरे मोड के लिए समीक्षा कर सकती हैं, जैसे कि LBW। साथ ही, कई तरह के आउट होने के मामलों में, अब निर्णयों का मूल्यांकन तार्किक, कालानुक्रमिक क्रम में किया जाएगा।

(ii) खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कदम उठाते हुए, टीमों को अब मैच से पहले पाँच कन्कशन सब्सटीट्यूट की घोषणा करनी होगी। अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान कन्कशन का पता चलता है, तो उसे कम से कम सात दिनों के लिए बाहर कर दिया जाएगा। घरेलू लीग भी पूर्णकालिक समान-से-समान चोट प्रतिस्थापन का परीक्षण करेंगी।

(iii) ICC ने बॉल पॉलिशिंग के लिए लार पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन स्वचालित बॉल रिप्लेसमेंट की आवश्यकता में ढील दी है। अंपायर अब यह आकलन करेंगे कि बॉल की स्थिति में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लार का जानबूझकर इस्तेमाल करने पर पांच रन की पेनल्टी लगेगी, जिससे खेल में अनावश्यक व्यवधान के बिना स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के प्रमुखों की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

27 जून 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के एमडी और सीईओ के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में वित्तीय स्वास्थ्य, ऋण वृद्धि, समावेशन रणनीतियों, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की गई, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके।

• मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना करते हुए शुरुआत की, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹1.04 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। कुल कारोबार ₹203 लाख करोड़ से बढ़कर ₹251 लाख करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध NPAs घटकर सिर्फ़ 0.52% रह गया। पूंजी पर्याप्तता 16.15% CRAR पर मज़बूत रही और कुल लाभांश बढ़कर ₹34,990 करोड़ हो गया।

• उन्होंने ऋण विस्तार को बनाए रखने के लिए जमा राशि जुटाने को मजबूत करने पर जोर दिया, PSBs से अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने और विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया। 1 जुलाई 2025 को एक नया वित्तीय समावेशन अभियान शुरू होगा, जो तीन महीने तक चलेगा और 2.7 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा। इसका फोकस KYC/री-KYC, दावा न की गई जमाराशियाँ और PM जन धन, PMJJBY और PMSBY जैसी प्रमुख योजनाओं पर है।

• ऋण के मोर्चे पर, सीतारमण ने बैंकों को अक्षय और टिकाऊ ऊर्जा वित्तपोषण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया - जिसमें छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर शामिल हैं - और कठोर अंडरराइटिंग मानकों को बनाए रखते हुए उभरते विकास क्षेत्रों का समर्थन करना चाहिए। PM धन धन्य योजना के माध्यम से कृषि ऋण पर प्रकाश डाला गया, जिसका लक्ष्य 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करना था।

Key Points:-

(i) MSME पोर्टफोलियो के तहत, 6 मार्च 2025 को लॉन्च किए गए नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल ने पहले ही 1.97 लाख लोन में 60,000 करोड़ रुपये का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, स्टैंड अप इंडिया के तहत 51,192 करोड़ रुपये के 2.28 लाख लोन और PM विद्या लक्ष्मी के तहत 1,751 करोड़ रुपये के 6,682 एजुकेशन लोन मंजूर किए गए। बैंकों को समावेशी क्रेडिट एक्सेस के लिए इन मॉडलों को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है।

(ii) ग्राहक अनुभव और नवाचार मुख्य एजेंडा बिंदु थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शिकायत निवारण बढ़ाने, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने, स्वच्छ शाखाएं बनाए रखने, रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाने और मेट्रो तथा कम सेवा वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भौतिक उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साइबर लचीलापन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

(iii) अंत में, सीतारमण ने बैंकों से आग्रह किया कि वे GIFT सिटी में अपनी उपस्थिति बढ़ाएं, ताकि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्त अवसरों तक पहुंच बनाई जा सके और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली तथा PM विश्वकर्मा जैसी प्रमुख योजनाओं में भागीदारी जारी रखी जा सके।

App and Web Portal

1. MoSPI ने आधिकारिक डेटा तक रीयल-टाइम पहुंच के लिए GoIStats ऐप लॉन्च किया।

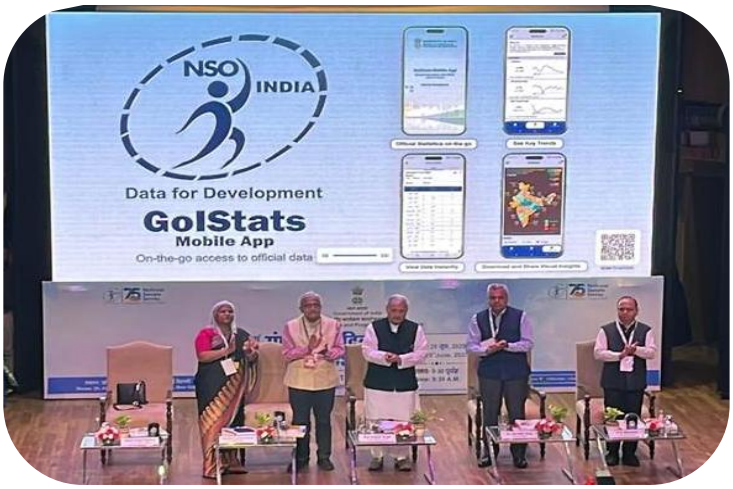

सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आधिकारिक तौर पर GoIStats मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSO) द्वारा विकसित, इस ऐप को नागरिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल, इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकारी आँकड़ों तक सहज, वास्तविक समय की पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• यह लॉन्च 29 जून, 2025 को हुआ, जो 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के रूप में भी चिह्नित किया गया, जो इसे भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है।

• केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने GoIStats ऐप लॉन्च किया, जिसमें सरकार के डिजिटल विजन के अनुरूप तकनीक-संचालित डेटा एक्सेस के माध्यम से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

• GoIStats ऐप में कई तरह की डेटा सेवाएँ हैं, जिसमें एक इंटरैक्टिव "की ट्रेंड्स" डैशबोर्ड शामिल है, जो GDP, मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी और बहुत कुछ पर दृश्य दिखाता है। यह डाउनलोड करने योग्य तालिकाएँ, CSV फ़ाइलें, इन्फोग्राफ़िक्स और मेटाडेटा प्रदान करता है। एक समर्पित "उत्पाद" अनुभाग उपयोगकर्ताओं को केवल एक टैप से आधिकारिक डेटा तक पहुँचने की अनुमति देता है, जो NSO प्रकाशनों की पूरी लाइब्रेरी और अपडेट के लिए पुश नोटिफिकेशन द्वारा समर्थित है।

Key Points:-

(i) वर्तमान में Google Play Store पर उपलब्ध GoIStats ऐप को रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों के भीतर 1,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसका फ़ाइल साइज़ सिर्फ़ 24 MB है। MoSPI ने पुष्टि की है कि व्यापक पहुँच और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही iOS संस्करण भी जारी किया जाएगा।

(ii) ऐप का लॉन्च "विकसित भारत 2047" विजन के तहत MoSPI की व्यापक डिजिटल सुधार रणनीति का हिस्सा है। मंत्रालय AI -आधारित सांख्यिकीय मॉडलिंग, डेटा सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा और आधुनिक संग्रह उपकरणों में निवेश कर रहा है। ऐप आम जनता के लिए डेटा को अधिक सुलभ और व्याख्या करने योग्य बनाकर इन प्रयासों का पूरक है।

(iii) लॉन्च से पहले, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने MyGov के साथ मिलकर 25 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक "इनोवेट विद गोआईस्टेट्स" नामक एक राष्ट्रीय हैकथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में युवाओं और डेटा पेशेवरों को वास्तविक डेटासेट का उपयोग करके विज़ुअलाइज़ेशन और एनालिटिक्स टूल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विजेताओं को ₹2 लाख तक की पुरस्कार राशि दी गई और सांख्यिकी दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ नवाचारों का प्रदर्शन किया गया।

IMPORTANT DAYS

1. राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून 2025 को मनाया गया।

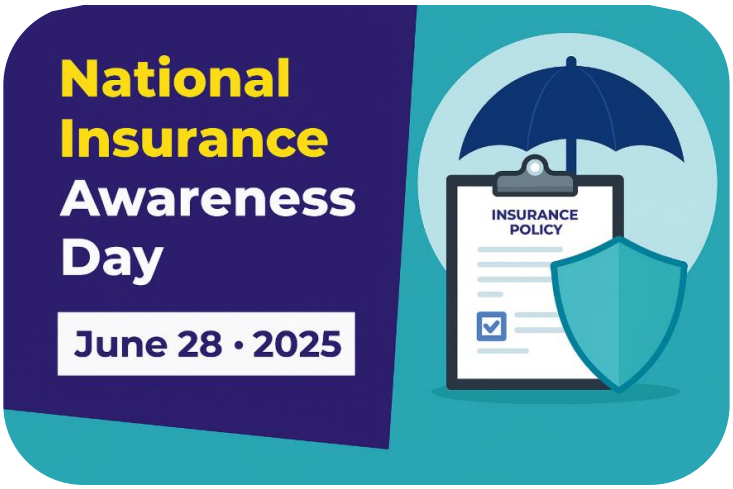

राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून को बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो एक वित्तीय उपकरण है जो व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों को अप्रत्याशित वित्तीय बोझ और आपात स्थितियों से बचाता है।

• यह दिन पूरे भारत में लोगों को अपनी मौजूदा बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन करने, उनकी कवरेज शर्तों को समझने और अपनी बदलती जरूरतों और जोखिमों के अनुरूप पॉलिसियों को अपडेट करने या खरीदने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

• बीमा बीमाकर्ता (बीमा प्रदाता) और बीमित व्यक्ति या संस्था के बीच एक कानूनी समझौते के रूप में कार्य करता है, जिसे पॉलिसी की शर्तों और शर्तों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह पॉलिसीधारक से बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरण सुनिश्चित करता है, अप्रत्याशित नुकसान के दौरान वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) ऐतिहासिक रूप से, भारत का औपचारिक बीमा क्षेत्र 1818 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल (WB) में स्थित है। इस घटना ने देश में संरचित जीवन बीमा के शुरुआती पदचिह्न को चिह्नित किया।

(ii) भारत में, बीमा पॉलिसियां आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पर्याप्त कर लाभ प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, पॉलिसीधारक धारा 80C के अंतर्गत जीवन बीमा प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं, जबकि पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त मृत्यु लाभ अधिनियम की धारा 10(10D) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं।

2. पूरे भारत में चिकित्सा पेशेवरों के सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 मनाया गया।

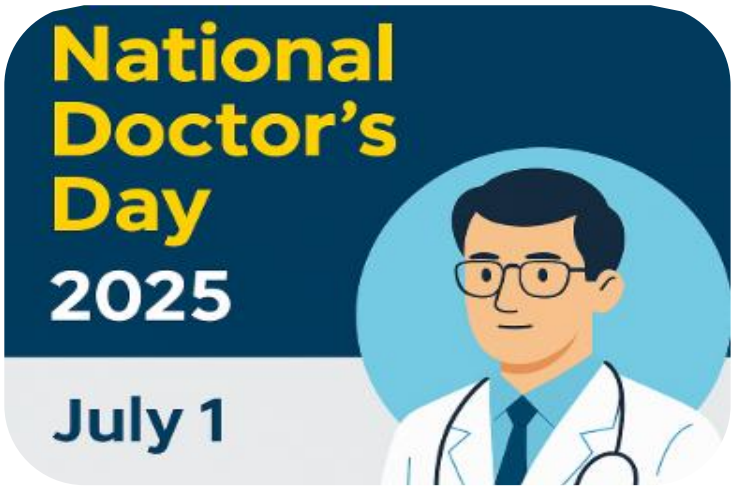

1 जुलाई, 2025 को भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया। यह दिन हर साल प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म और निधन 1 जुलाई को हुआ था।

• राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 का विषय है "मुखौटे के पीछे: चिकित्सकों को कौन ठीक करता है?", जो डॉक्टरों द्वारा सामना की जाने वाली भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करने पर एक राष्ट्रीय संवाद शुरू करना है, खासकर COVID-19 जैसे हाल के स्वास्थ्य संकटों के दौरान बढ़े हुए तनाव के बाद।

• राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1991 में भारत सरकार द्वारा डॉ. बी. सी. रॉय की याद में मनाया गया था, जिन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

उनका जन्म और मृत्यु एक ही तारीख - 1 जुलाई - को होना इस दिन को प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली बनाता है और भारत के चिकित्सा समुदाय के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि है।

Key Points:-

(i) इस दिन चिकित्सा संस्थान, अस्पताल और सरकारी निकाय स्वास्थ्य जांच शिविर, जागरूकता सेमिनार, रक्तदान अभियान और उत्कृष्ट डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और राज्य स्वास्थ्य विभाग भी मरीजों की देखभाल के प्रति डॉक्टरों के समर्पण को मान्यता देते हुए विशेष अभियान चलाते हैं।

(ii) 2025 तक, भारत में डॉक्टर-से-जनसंख्या अनुपात 1:811 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 1:1000 के मानक से बेहतर है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह दिन चिकित्सा अवसंरचना की कमी, थकान, लंबे समय तक काम करने और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर बढ़ते हमलों के बारे में भी चिंता व्यक्त करता है।

(iii) राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 बेहतर चिकित्सा नीतियों, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश, प्रशिक्षण और उचित कार्य स्थितियों की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिवस डॉक्टर-रोगी संबंधों में विश्वास को मजबूत करता है और जनता से पेशे के पीछे की मानवता को पहचानने और देखभाल करने वालों को समर्थन देने का आग्रह करता है।

BOOKS & AUTHORS

1. जगदीश शुक्ला ने जलवायु और अराजकता सिद्धांत पर संस्मरण "ए बिलियन बटरफ्लाईज़" का विमोचन किया।

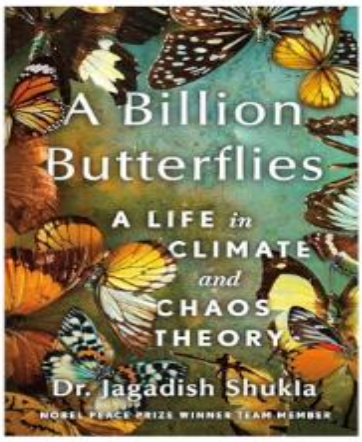

प्रसिद्ध भारतीय मौसम विज्ञानी जगदीश शुक्ला ने हाल ही में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित "ए बिलियन बटरफ्लाईज़: ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड कैओस थ्योरी" शीर्षक से एक संस्मरण लिखा है। यह पुस्तक जलवायु गतिशीलता, पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान के विकास को समझने में उनकी व्यक्तिगत और वैज्ञानिक यात्रा का वर्णन करती है।

- **पुस्तक में, शुक्ला ने एक ग्रामीण भारतीय गांव से एक अग्रणी वैश्विक जलवायु वैज्ञानिक बनने तक के अपने उत्थान को साझा किया है। उन्होंने "बिलियन बटरफ्लाई" प्रयोगों की अवधारणा पेश की, जिसने मौसम की अप्रत्याशितता के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी, जलवायु पूर्वानुमान में अराजकता सिद्धांत की भूमिका पर जोर दिया।**

Key Points:-

(i) संस्मरण जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उसी वर्ष, उन्हें मौसम विज्ञान में सर्वोच्च वैश्विक सम्मान, प्रतिष्ठित IMO पुरस्कार मिला।

(ii) विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए जगदीश शुक्ला को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह वर्तमान में अमेरिका के वर्जीनिया स्थित जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप

में कार्यरत हैं तथा वैश्विक जलवायु नीति और अनुसंधान में एक प्रभावशाली आवाज बने हुए हैं।

Static GK

ESIC (Employees' State Insurance Corporation)	महानिदेशक : अशोक कुमार सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
MoRTH	केंद्रीय मंत्री: नितिन गडकरी	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
MoSPI	मंत्री: राव इंद्रजीत सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Bangladesh	अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन	मुद्रा: बांग्लादेशी टका
UNESCO	महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले	मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
ICC	स्थापना: 1909	मुख्यालय: दुबई